[श्री रामानन्द यादव]

से ख़राब वस्तुएं दी जाती हैं आटा जो खट्टा होता है उसकी रोटी हम को सप्लाई की जाती है। कैन्टीन में जो फ्रूट हम को मिलता है, बाजार में जो सब से रद्दी फ्रूट बिकता है, वैसा कैंटीन में बिकता है। जो सरकार अपनी नाक के नीचे...

MR DEPUTY CHAIRMAN: Now, Special Mentions.

श्री रामानन्द यादव : . . . इन बातों को बर्दाश्त करती है वह इस देश के शासन को कैसे चलाएगी, मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप कम से कम हम लोगों की यह जो छोटी सी सुविधा है इसके सम्बन्ध में अपना ध्यान दें।

REFERENCE TO ALLEGED DELAY IN ATTENDING TO TELEPHONE COMPLAINTS

श्री **नागेश्वर प्रसाद शाही** (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, टेलीफोन के बारे में मुझे कहना है। नार्थ ऐवेन्यू का टेलीफोन सिस्टम इतना खराब पहले कभी नहीं था। नार्थ ऐवेन्यू का टेलीफोन इतना खराब है इसकी शिकायत की गई पर टेलीफोन विभाग के मंत्री जी के कान पर जूं नहीं रेंगी।

श्री सीता राम केसरी (बिहार): कौन है टेलीफान मंत्री, हमने नहीं देखा है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : और उनको चिट्ठी भी लिखते हैं तो जवाब नहीं देते . . (*Interruptions*) . . यह पार्टी लेवल से ऊपर की बात है। उपसभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर एम० पी० के टेलीफोन की शिकायत नहीं अटेण्ड होगी तो आम पब्लिक को कौन अटेण्ड करेगा? अगर टेलीफोन मिनिस्टर इस चीज को नहीं देखते हैं तो कैसे काम चलेगा?

SHRI JAHARLAL BANERJEE (West Bengal): Sir, even when the Parliament is in session, there is no water in the bathroom. The Administration can provide us with this minimum facility.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We wil] take note of what the hon. Members have said and take necessary action.

REFERENCE TO FLOOD SITUATION IN BIHAR

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त (बिहार): उपसभापति महोदय, इस सरकार का ध्यान मैं एक जनहित की बात की ओर खींचना चाहता हूं जो बिहार की बाढ़ से सम्बधित है। आकाशवाणी एवं कई अखबारों में बिहार की बाढ़ के विषय में बराबर समाचार आ रहे हैं और खास कर बिहार का 'सर्चलाइट' अखबार जिसमें सब से बड़ी न्यूज है "फ्लड इन दरभंगा ऐंड सहरसा टाउन्स" और फिर उसी में "गवर्नर्स अपील फार रिलीफ" निकली है। इस प्रकार आप देखें कि बिहार में काफी बाढ़ आ गई है। वहां पर सात जिले इस बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। दो कमीश्नरी शहर, दरभंगा और सहरसा— इससे प्रभावित हो गये हैं और वहां के इन सात जिलों के अन्दर जो 28 प्रखंड हैं उनकी जनता इससे परेशान है। इन सारे जिलों की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। वहां के मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर के अनुसार 40 लाख की आबादी इस

[श्री राम लखन प्रसाद गुप्त]

बाढ़ से प्रभावित है और 8 करोड़ का नुकसान इससे हो चुका है । इसके मुताबिक सारे बिहार में काफी चिन्ता है । राज्यपाल महोदय श्री जगन कौशल जी ने भी सभी पार्टियों की मीटिंग की और यहां तक कि विरोधी पार्टी के नेता और जो दूसरे वालंटरी आर्गेनाइजेशन्स थे, उन सारे लोगों की मीटिंग हुई और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपील की घोषणा की गयी है । वहां के मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने भी सरकार से, केन्द्रीय सरकार से अपील की है...

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : आपके मंत्रिगण तो लव लेटर्स लिख रहे हैं एक दूसरे को और वहां बाढ़ आ रही है। पहले इसका समाधान तो कीजिए ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): वह लव लेटर्स अगर आप देखना चाहते हों तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं ।

श्री श्याम लाल यादव : आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं ?

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभापति महोदय, यही बात स्पेशल मेंशन के रूप में मैंने आपके सामने पेश की थी कल और आपने उसको अस्वीकार कर दिया था । एस ओ एस बिहार के मुख्य मंत्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था और तमाम संस्थाओं को लिखा था, लेकिन आपने उस बात को यहां उठाने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया । लेकिन उसी बात को आज आपने कबूल किया है और उठाने की इजाजत दी है । तो यह किस आधार पर किया गया है । कौन सा मापदंड आप का है । एक सदस्य एक बात कहता है तो उसे आप रिजेक्ट कर देते हैं और फिर वही बात जब दूसरा सदस्य उठाता है तो आप उसको कबूल कर लेते हैं । तो इसके लिए भी कोई एक स्टैण्डर्ड रहना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि वह यह बात क्यों उठा रहे हैं । यह बात वह ठीक ही उठा रहे हैं । एक यह बर्निंग इश्यू है बिहार का । वहां की एक भीषण समस्या है । लेकिन यही बात मैंने कल उठायी थी और आपके ही दस्तखत से मेरे पास आ गया "नाट एडमिटेड" । तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है ?

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य ने आज एक बात उठायी है और पहले भी ऐसी बात उठायी है सदन की प्रक्रिया के बारे में, पहले तो मेरा निवेदन यह है कि कौन स्वीकार हुआ और कौन स्वीकार नहीं हुआ यह बात कृपा कर माननीय सदस्य सदन में न उठाया करें । आप चेयरमैन महोदय से मिल कर अपनी बात बता दें ताकि सदन का समय इस में न जाय । (*Interruptions*) सुनिये । बात ऐसी है कि चाहे मैं कहूं या सेक्रेटरिएट कहे या चेयरमैन साहब कहें, सब एक ही बात है । एक प्रक्रिया के मुताबिक सब को चलना है । उसके अनुसार आपको समझाया जाएगा । यदि उससे आपको सन्तोष नहीं होगा तो आगे बहस की जाएगी । लेकिन कृपया सदन में इस प्रकार की बात कि मेरा यह मेंशन स्वीकार हुआ या नहीं हुआ, यह न उठायें । पहले भी आप इस प्रकार की बातें कह चुके हैं और सब बातें नोट की जाती हैं, लेकिन मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि सदन में यह बात आप न उठायें और इस तरह की बातों का निराकरण चेयरमैन महोदय के चेम्बर में करें ।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त : वहां की नदियों बाघमती, कमलावालान, अघवाड़ा ग्रुप आफ रीवर्स, और जो दूसरी नदियां हैं उन सबमें काफी बाढ़ आ गई है और इतना ही नहीं, यह भी सूचना आयी है कि हैजे का भी प्रकोप दरभंगा में काफी बढ़ गया है। मधुबनी जिले के अन्दर भी हैजे का प्रकोप हो गया है। इन सारे जिलों में— दरभंगा, समस्ती पुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्वी चंपारन और पश्चिमी चंपारन— इन सारे स्थानों में आज भुखमरी को भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से बिहार को अविलम्ब सहायता मिले और उस की रोकथाम के लिये भी कुछ व्यवस्था हो। वहां पर पीड़ितों के लिए दवा की व्यवस्था हो और इसके साथ ही बिहार की इस स्थिति का सरकार अपना एक वक्तव्य दे।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूरे देश के पैमाने पर जो बाढ़ की भयंकर विभीषिका आई है जिसके कारण लाखों एकड़ जमीन व फसल नष्ट हो गई है और जिसके कारण लाखों लोगों की जिन्दगी बिलकुल तबाही के कगार पर खड़ी है, उस ओर दिलाना चाहता हूं।

उपसभापति महोदय, इस बाढ़ के सम्बन्ध में जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं, यह कोई बिहार का ही प्रश्न नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की ही केवल समस्या नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, बंगाल के अन्दर पूरे देश के पैमाने पर बाढ़ आई हुई है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि जब पूरे देश के अन्दर बाढ़ आई हुई है, आज तक केन्द्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य भी या प्रधान मंत्री बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने नहीं गये। जैसे रोम में आग लगी हुई थी और नीरो चैन की बंसी बजा रहा था, वही हाल जनता पार्टी का है। पूरी की पूरी जनता पार्टी अपने अन्दरूनी झगड़ों के अन्दर व्यस्त है, राष्ट्र का ध्यान इन्होंने बिलकुल भुला दिया है।

उपसभापति महोदय, करोड़ों लोग, करोड़ों की सम्पत्ति बरबाद हो गई है। लाखों एकड़ जमीन और फसल नष्ट हो गई। हजारों गांव बह गये। उत्तर प्रदेश के अन्दर बहराइच, देवरिया, गोरखपुर के इलाके में घाघरा के तट के सारे गांव सारे जिले बिलकुल बाढ़ की चपेट में आ गये।

आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 1975 में 471 करोड़ रुपए का नुकसान बाढ़ से हुआ था। 1976 में 888 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 1977 में 1131 करोड़ रुपए का नुकसान बाढ़ से हुआ था। इस साल उससे भी बड़ी बाढ़ की विभीषिका है और करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान बाढ़ से होगा। जैसी कि वाटर कमीशन आफ इंडिया की रिपोर्ट है, 3834 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वाटर कमीशन आफ इंडिया के अनुसार प्रति वर्ष 146 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ तो हर साल आएगी जब तक कि यह सरकार अन्तर्राष्ट्रीय ऐग्रीमेंट नहीं करती है। जब तक दिल्ली की सरकार नेपाल सरकार के साथ हिमालय से निकलने वाली नदियों के सम्बन्ध में ऐग्रीमेंट नहीं करती तब तक उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तथा आसाम को बाढ़ की विभीषिका से नहीं बचाया जा सकता है।

आदरणीय उपसभापति महोदय, पिछली सरकार ने नेपाल सरकार के साथ जल-कुण्डी योजना के सम्बध में, भैंसालोटन

बांध के सम्बन्ध में, पंचेश्वर बांध के सम्बन्ध में, करनाली के सम्बन्ध में समझौता वार्ता चलाई थी और नेपाल सरकार का प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और यहां का प्रतिनिधिमंडल नेपाल गया था । लेकिन जनता सरकार ने उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं किया जिनको पिछली सरकार ने तेजी से करना प्रारम्भ कर दिया था । भालू बांध योजना पिछली सरकार के अन्तर्गत स्वीकार हो गई थी, इन योजनाओं के ऊपर करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च होगा। यदि ये योजनायें जो नेपाल सरकार से ऐग्रीमेंट के अन्तर्गत स्वीकार हुई हैं इनको कार्यान्वित कर दिया जाए, भालू बांध की योजना को पूरा कर दिया जाएं, पंचेश्वर और जलकुण्डी तथा करनाली योजना को अमली रूप दे दिया जाए, तो बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सकता है ।

आदरणीय उपसभापति महोदय, जिस प्रकार गोविन्दसागर के पानी को बांधकर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के मरुस्थल इलाके को हरा-भरा कर दिया गया है, उसी तरह से अगर हिमालय से निकलने वाली नदियों पर इन योजनाओं को इम्प्लीमट कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान यानी हिमालय और गंगासागर के बीच जो भयंकर गरीबी, बरबादी एवं दरिद्रता है, यह इलाके भी इसी तरह हरे-भरे हो जायेंगे । बिजली और पानी का इस्तेमाल इन इलाकों के विकास के लिए हो सकेगा । मैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल से और प्रधान मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस इलाके का, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और विशेषकर उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका जलमग्न है, जो बहराइच से लेकर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी से लेकर दरभंगा के बीच में सारा का सारा इलाका जलमग्न है, ऐसे इलाकों का प्रधान मंत्री दौरा करें या कैबिनेट मंत्रियों में जो कि दिन रात पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति का नाम लेकर अपने को जिन्दा रखे हुए हैं, ऐसे लोगों को वहां भेजा जाए । मैं सरकार से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि वह नेपाल सरकार से हिमालय से निकलने वाली नदियों के सम्बन्ध में जो पिछली कांग्रेस सरकार ने ऐग्रीमेंट्स किये थे उन योजनाओं पर उनको क्रियान्वित करने के लिए एक टाइम बाउंड, योजना बद्ध तरीके से काम करें ।

आदरणीय उपसभापति महोदय, दूसरी बात हमें कहनी है कि जो गंडक परियोजना है जो कि भैंसालोटन से निकल कर उत्तरी बिहार में जाती है, इस गंडक योजना के कारण दो-तीन सौ मील लम्बी नहर बनी हुई है और इसके कारण ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है । नहरों के बनने के कारण जगह-जगह 25 मील, 20 मील, 10 मील के जो बांध बन गए हैं इसके कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी नहीं जाता है । अगर एक ही दिन वर्षा हो जाएगी तो इससे भयंकर बर्बादी हो जाएगी । फसल नष्ट हो जाएगी और अगले साल के लिए कोई फसल नहीं होगी । इन योजनाओं को पूरा करने के लिए जो भारत सरकार और नेपाल के बीच समझौता हुआ है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सदन के अंदर पूरे एक दिन इस बाढ़ की समस्या पर बहस करें और जो पिछली सरकार ने एग्रीमेंट किया था उसके मुताबिक 1200 करोड़ रुपये का खर्चा आता है तो इस बजट का इमरजैंसी बजट में प्रोविजन करने की व्यवस्था करें ताकि आने वाले जमाने में बाढ़ न आ सके । वाटर कमीशन की रिपोर्ट है कि अगर यह इकरारनामा इम्पलीमेंट कर दिया जाता है तो तीन मीटर पानी नीचे बैठ जाएगा और तीन मीटर पानी नीचे आने का परिणाम होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम के इलाकों से, यानी पश्चिम से जो पानी पूर्व को जाता है उसके कारण इन इलाकों में बाढ़ विभीषिका नहीं होगी । उत्तर प्रदेश

[श्री कल्पनाथ राय]

और बिहार के जो इलाके हैं जिन्हें अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ईर्ष्याद्वेष का शिकार होना पड़ा और जो इलाके हमेशा आजादी की लड़ाई में आगे रहे और जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी में हिन्दुस्तान के निर्माण में काम किया ऐसे अभागे इलाकों को बाढ़ की विभीषका से यहां की भूखी नंगी जनता को, इकरारनामे का इम्पलीमेंट करके, राहत दे सकेंगे ।

REFERENCE TO SHORTAGE OF CEMENT IN THE COUNTRY

श्री सवाई सिंह सिसौदिया (मध्य प्रदेश): मान्यवर, जन- उपयोगी वस्तुओं के अभाव की दुर्दशा की चर्चा अभी सदन में की गई है और आए दिन विरोधी दल की ओर से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है लेकिन स्थिति बद् से बदतर होती जा रही है ।

मान्यवर, मैं इस समय सीमेंट के अभाव की चर्चा करना चाहता हूं । सीमेंट का जहां तक संबंध है हमारे देश में मोहनजोदारो के जमाने से सीमेंट बनता आ रहा है । मशीन से बनने का सिलसिला 1914 से शुरू हुआ है । 76-77 में 20 मिलियन टन सीमेंट हमारे मुल्क में पैदा हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि तमाम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर, सहूलियत के साथ सीमेंट उपलब्ध हो रहा था लेकिन आश्चर्य होता है कि आज सीमेंट का अभाव लोगों को इतना जबर्दस्त परेशान किये हुए है कि आवश्यक निर्माण कार्य भी रोकने पड़े हैं और इसका कारण भी जानने की कोशिश नहीं की जा रही है । मेरे पूर्व सहयोगी ने जो बताया ठीक ही बताया कि जनता पार्टी का शासन अपने अन्तरद्वन्द में इतना घिरा हुआ है कि न तो उनके पास इसे सोचने का समय है और न उनमें इतनी क्षमता ही रह गई है कि वह जनता की कठिनाईयों को दूर करें और निश्चित योजना बनाकर उस पर अमल करें ।

मैं सीमेंट के बारे में निवेदन कर रहा था कि आज यह सोचा जा रहा है कि विदेशों से सीमेंट आयात किया जाए। हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में जिन-जिन वस्तुओं के बारे में हम स्वावलम्बी थे, हम आत्मनिर्भर थे उन सब का आयात किया जा रहा है । जैसे खाने के तेल की कमी हुई तो उसका आयात शुरू कर दिया । कोयला विदेश से मंगाया जा रहा है, आयरन स्टील मंगाया जा रहा है । आज से एक साल पहले हमारे यहां ये चीजें जरूरत से ज्यादा थीं और जिनका हम निर्यात करते थे आज उनका आयात किया जा रहा है । जो विदेशी मुद्रा का भंडार पिछली सरकार छोड़ गई थी उसको समाप्त किया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि जिन चीजों की कमी हुई है उन चीजों का उत्पादन मुल्क में करें और जो दूसरी समस्या आर्थिक समस्या है इस पर भी यहां विचार करें । इन सब चीजों पर गहन गम्भीरता के साथ विचार करके निश्चय करने का कोई समय इस शासन के पास नहीं है । मैं सरकार से दो चीजें निवेदन करना चाहता हूं, एक तो यह कि 1976-77 के वर्ष तक आठ लाख रुपये के सीमेंट का निर्यात किया था ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम को इस बात को याद रखना चाहिए कि आज हमारे देश में क्या स्थिति हो रही है ? राजस्थान में जो कैनाल प्रोजेक्ट है वह पांच करोड़ रुपयों की योजना है । वहां पर सीमेन्ट के उपयोग के लिए शासन की ओर से सीमेन्ट का इन्तजाम किया गया है । लेकिन इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही हैं कि वहां से दो मीलियन टन सीमेण्ट का स्मग्लिग हो रहा है । एक तरफ तो हमारे देश में सीमेन्ट की कमी है और सीमेन्ट का इस्तेमाल हम अपनी योजना पर करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार से सीमेन्ट का स्मग्लिग चल रहा है । इन खराबियों